भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1654
सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

प्रवेश स्तर पर भर्ती में गिरावट

1654. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस वर्ष देश में प्रवेश स्तर पर भर्ती (फ्रेशर्स) में गिरावट की जानकारी है जैसाकि विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं और एचआर परामर्शदाता फर्मों द्वारा सूचित किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो इस गिरावट के लिए कैम्पस भर्ती के प्रति उद्यमों द्वारा सावधानी बरतने के किसी उल्लेखनीय दृष्टिकोण सहित किन कारणों की पहचान की गई है;
- (ग) क्या सरकार रोजगार बाजार में, विशेषकर स्नातकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए कदम उठा रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या बढ़ती कौशल आवश्यकताओं और वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर नए स्नातकों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए कोई पहल की गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्नातकों हेतु रोजगार का दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 49.7% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 57.5% हो गया है।

युवाओं सहित सभी के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि कार्यावित्त कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस भविष्य के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना है।

सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लाई है जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है। मध्य और माध्यमिक विद्यालय में कम उम्र में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके गुणवत्ता पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारु रूप से एकीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। बजट 2024-25 में, 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, रोजगार संबंध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल की गई जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ईएलआई योजना, रोजगार के औपचारीकीकरण/सृजन के लिए विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में कई पहलों की घोषणा के साथ रोजगार आधारित विकास को भी प्राथमिकता दी गई है।